IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 4, October-December, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन के प्रभावों का विश्लेषण

शोधार्थी
सरोज प्रमिला
मध्यकालीन और आधुनिक भारत
डॉ० भीमरॉव अम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)–212601
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
शोध निर्देशिका
प्रो० डॉ० मीरा पाल
विभागाध्यक्ष–इतिहास
डॉ० भीमरॉव अम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)–212601
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिकता है यह वस्तुएँ तो सिर्फ हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है पर सही गलत में अंतर और अच्छी प्रगतिशील सोच विचार के लिए आवश्यक अच्छी शिक्षा है। हमारी भारत सरकार ने कई सारी शिक्षा नितियाँ लाई और उसमें भी कई बदलाव हुए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी, लचीला और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक प्रयास है। इसे 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। नीति का उद्देश्य शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़वा देना है। नीति में पाठ्यचर्या को 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तित किया गया है, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएग तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक बनाने की योजना है, इसमें शिक्षकों को अधिक स्वायत्ता, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, और व्यावसायिक शिक्षा के समावेश पर भी जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है नीति ने शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश की जीडीपी 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

इस नीति के कार्यान्वयन से बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले है जिनमें सकारात्मक लाभों के साथ–साथ चुनौतियाँ और नकारात्मक प्रभाव भी शामिल है।

नीति के लागू होने से छात्रों को उनकी सीखने की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन से छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता बढ़ी है। इससे ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के बीच शिक्षा प्राप्ति में असमानता घटने लगी है। बहु–विषयक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा के समावेश से छात्रों को अपनी रूचि के विषय चुनने और व्यवहारिक कौशल सीखने का अवसर मिला है। परिणामस्वरूप 21वीं सदी के रोजगार और नवाचार की मांगो के अनुरूप तैयार होने में छात्रों की मदद हो रही है।

नीति शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। इसमें शिक्षकों को Learning Facilitator बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहु–विषयक पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन सुधार जैसे प्रावधान शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्धारण में भागीदारी देते है। साथ ही नीति ने शिक्षकों का प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास भी सुनिश्चित किया है, जिससे वे नई शिक्षा–पद्धतियों के अनुसार अपने कौशल विकसित कर रहे हैं। नीति में 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड को अनिवार्य करने की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

अभिभावकों की दृष्टि से, मातृभाषा में शिक्षा और अंग्रेजी के साथ–साथ स्थानीय भाषाओं का समावेश सकारात्मक रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के माता–पिता के भरोसे में वृद्धि हुई है कि उनके बच्चे सहजता के शिक्षा ग्रहण कर सकते है। साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार और बोर्ड परीक्षाओं के विकल्प से तनाव कम हुआ है। नीति ने निजी स्कूलों को भी रेगुलेट करने की पहल की है, जिससे अभिभावकों को शिक्षा की गुणवत्ता और खर्च पर संतुलन की उम्मीद बढ़ी है। इन परिवर्तनों से परिवारों में शिक्षा के प्रति विश्वास वर्धित हुआ है।

NEP के लागू होने से शिक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव आए है। उच्च शिक्षा में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) गठन, स्नातक में मल्टीपल एंट्री–एग्जिट प्रावधान और शैक्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी प्रणालियाँ आएगी, जिससे विश्वविद्यालय प्रणाली में लचीलापन बढ़ा है। नीति ने उच्च शिक्षा में GER (Gross Enrollement Ratio) को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। स्कूल शिक्षा के लिए नवाचार मिशन (जैसे NIPUN BHARAT) और समग्र शिक्षा योजना (समग्र शिक्षा 2.0) जैसे कार्यक्रम चालू हुए है। साथ ही केन्द्र और राज्य मिलकर नीति के कार्यान्वयन के लिए सहयोग कर रहे है क्योंकि शिक्षा समान सूची में होने के कारण दोनों स्तर जिम्मेदार है।

NEP में 6% GDP व्यय करने की बात है, लेकिन व्यावहारिकता में यह बड़ी चुनौती बनी हुई है। मार्च 2025 में प्रस्तुत

संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 2021–22 में भारत का कुल शिक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 4.12% था, जो नीति के लक्ष्य से काफी कम है।

अंडर–फंडिग के कारण योजनाओं का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन रूकावटें कर रहा है। शिक्षक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएँ प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक संकटपूर्ण स्थिति बना हुआ है। नीति द्वारा प्रस्तावित 'सबसे अधिक पाँच वर्षीय आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था के बावजूद इस स्तर पर कुशल शिक्षकों की भारी कमी है। विशेषज्ञों के अनुसार, ''प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, इसलिए इसकी व्यवस्था के कार्यान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ है।

NEP में तीन–भाषा सूत्र और मातृभाषा में पढ़ाई के प्रावधानों ने कुछ राज्यों में सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस छोड़ दी है। दक्षिणी राज्यों ने 'त्रिभाषा सूत्र' को हिन्दी–प्रमुखतावाद समझते हुए इसका विरोध किया है। नीति आलोचकों का यह भी मानना है कि इसे संसद की मंजूरी नहीं दी गई, जबकि पिछली शिक्षा नीति 1986 संसद द्वारा पारित थी। साथ ही विदेशी विश्व–विद्यालयों को शामिल करने से उच्च शिक्षा मंहगी होने की आशंका व्यक्त की गई है; कुछ शिक्षाविदों ने कहा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से शिक्षा महंगी और असार्वजनिक हो सकती है।

इससे निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच कठिन हो सकती है। इसके अलावा नीति से शैक्षणिक संरचनाओं में बदलाव के कारण पाठ्यक्रम पुनर्संयोजन और मूल्यांकन प्रणाली में असमंजस बना हुआ है, जिसमें अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों में अनिश्चितता बढ़ी है।

डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग प्रोत्साहित करने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी ने समान शिक्षा में बाधा डाली है। कोविड–19 के बावजूद ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार हुआ है, पर दूर–दराज के विद्यालयों में पर्याप्त तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप डिजिटल विभाजन गहरा गया है। साथ ही पाठ्येतर गतिविधियों एवं स्किल डेवलपमेंट की सुविधा न होने के कारण नीति के ''व्यावहारिक कौशल'' घटकों को लागू करना मुश्किल हो रहा है। इन सब कारणों से नीति के कई सकारात्मक विचार व्यवहार में पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहे हैं।

नीति के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश देने से निजीकरण की आशंका है। इससे शिक्षा महँगी हुई तो सकल पढ़ाई का सामाजिक आधार कमजोर होगा कुछ विश्लेषको के अनुसार इससे देश के प्रतिभाशाली शिक्षकों का पलायन भी बढ़ सकता है, जिससे देश में दक्ष मानवशक्ति और भी कम हो जाएगी।

यदि 6% लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं हुआ तो अविकसित क्षेत्रों और ग्रामीण छात्रों के लिए सुविधाएँ और ज्यादा कम हो जाएंगी। सांविधिक रूप से 'समान शिक्षा'' का अधिकार है, पर यदि संसाधन कम पड़े; तो सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा तक पहुँच प्रभावित होगी। यह नीति के समावेशी दृष्टिकोण को कमजोर करने वाला दुष्प्रभाव हो सकता है।

अभी भी सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता निजी स्कूलों से बहुत पीछे है। यदि राज्य NEP के सुधारों को सरकारी स्तर पर पूरी गति से लागू नहीं करते, तो अमीर–गरीब में शिक्षा का अन्तर बढ़ सकता है। उदाहरणस्वरूप, मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाने तक इंग्लिश माध्यम छात्रों की कठिनाइयाँ बढ़ सकती है।

समाधान यह है कि नीति के लक्ष्य (6% GDP) की पूर्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय को हर बजट सत्र में शिक्षा आवंटन बढ़ाना चाहिए। संसदीय समिति ने भी सुझाव दिया है कि शिक्षा मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि मांगनी चाहिए ताकि NEP 2020 के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य का मिश्रित समन्वय बढ़ाकर बजटीय अंतर को कम करना होगा।

शिक्षकों को नवाचारों के लिए तैयार करने हेतु तत्काल प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना अनिवार्य है एकीकृत 4 वर्षीय बी.एड कार्यक्रम शीघ्र लागू किया जाए और वर्तमान शिक्षकों के लिए ऑनलाइन/आधुनिक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाए। त्रिभाषा सूत्र को लागू करते समय राज्यों की संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना चाहिए। मातृभाषा माध्यम की शिक्षा से लाभ लिया जाए। इससे मातृभाषा पठन का भरोसा बढ़ेगा और विरोध कम होगा।

दूरदराज के क्षेत्रों में ई–लर्निंग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार हो। सस्ते स्मार्ट उपकरणों और डिजिटल पाठ्यसामग्री पर निवेश बढ़ाया जाए। सार्वजनिक–निजी भागीदारी कौशल कक्षाएं खोलकर व्यावहारिक शिक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। केन्द्र और राज्य मिलकर नीतियों की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठके और कार्यशालाएँ आयोजित करें। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने बताया विभिन्न समय पर मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन में NEP 2020 पर चर्चा हुई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इसने शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर उसे कौशल–आधारित, लचीला और समग्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यद्यपि वित्तीय बाधाएं और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन 'निपुण भारत' और 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' जैसी पहले उम्मीद की किरण जगाती हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए, तो यह नीति निश्चित रूप से भारत को एक ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में बदल सकती है।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक विश्लेषण डॉ. बी. के. अग्रवाल और डॉ. एम. के. सिंह (विद्या पब्लिशर्स)
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन और चुनौतियाँ डॉ. आर. एस. तिवारी (डिस्कवर प्रकाशन)
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विद्यालयी शिक्षा का नया स्वरूप प्रो. रमेश चंद्र (फीनिक्स पब्लिकेशन)
4. नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय शिक्षा का भविष्य डॉ. संजय वर्मा (ओरिएंट ब्लैकस्वॉन)
5. NEP 2020 : प्राथमिक और उच्च शिक्षा में बदलाव डॉ. नीलम श्रीवास्तव (संपादक) (कल्याणी पब्लिशर्स)
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: बहुविषयक शिक्षा की ओर प्रो. एस. एन. गुप्ता (आर्या पब्लिकेशन)
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय दृष्टिकोण डॉ. आलोक कुमार (सार्थक प्रकाशन)
8. NEP 2020 का शिक्षा पर प्रभाव डॉ. पी. के. मिश्रा (प्रभात प्रकाशन)
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षक शिक्षा में सुधार डॉ. सुमन लता (साहित्य भवन)
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक व्यापक समीक्षा डॉ. राम गोपाल (अजय प्रकाशन)

पत्रिकाएँ / जर्नल

1. शैक्षिक चिंतन (Shikshik Chintan) प्रो. दिनेश शर्मा
2. शिक्षा मंथन (Shiksha Manthan) डॉ. अंजना सिंह (संपादक)
3. पाठशाला (Pathshala) डॉ. आर. के. सिंह
4. नया शिक्षक (Naya Shikshak) राज्य SCERT टीम
5. उच्च शिक्षा जर्नल (Uchch Shiksha Journal) विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान